



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 13 जून, 2003/23 ज्येष्ठ, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, ३० मई, 2003

संख्या य००१०-इ(३) ३५/९७.— कण्डाघाट क्षेत्र, जो ग्राम पंचायत श्रीनगर, जिला सोलम का भाग है, को समसंबंधीय अधिसूचना संख्या [तारीख ११-११-१९९८ द्वारा हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (ट) के अधीन, हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, १९८७ के प्रयोजनों के लिए नगरीय क्षेत्र घोषित किया गया था;

और कण्डाघाट क्षेत्र के निवासियों ने उक्त अधिसूचना को वापिस लेने के लिये [सरकार को अभ्यावेदन किया है;

और सरकार ने कण्डाघाट क्षेत्र के निवासियों की मांग पर विचार और परीक्षण किया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९६८ की वारा २० के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना को तुरन्त प्रभाव से विखिण्डत करते हैं, परन्तु हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, १९८७ के अधीन, उक्त क्षेत्र में अधिकारिता रखने

वाले विभिन्न न्यायालयों और अन्य प्राधिकरण में संस्थित सामने, यदि कोई हो, उक्त अधिनियम के उपनिषदों के अनुसार निपटाए जाएंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान मंचिव (शहरी विकास)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-E(3)-35/97, dated 30th May, 2003 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th May, 2003

No. UD-E-(3)-35/97.—Whereas the area of Kandaghat, a part of Gram Panchayat, Sirinagar, District Solan was declared as urban area for the purpose of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 under clause (k) of section 2 of the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 vide notification of even number dated 11-11-1998;

And whereas residents of the Kandaghat area have represented to the Government for withdrawal of the said notification;

And whereas, the Government considered and examined the demand of the residents of the Kandaghat area.

Now, in exercise of the powers conferred by clause (k) of section 2 of the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 readwith section 20 of the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to rescind the said notification with immediate effect, provided that the cases, if any, instituted under the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 in various courts and other authority, having jurisdiction over said area, shall be disposed off in accordance with the provisions of the said Act.

By order,

Sd/-
Principal Secretary (UD).